

पृष्ठभूमि

- दिशा योजना के तहत, कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का अब अखिल भारतीय स्तर पर विस्तार किया गया है।
- यह एक बहु-हितधारक, प्रगतिशील और परिवर्तनकारी दृष्टिकोण की परिकल्पना करता है जो कानूनी अधिकारों, अधिकारों और प्रासंगिक कानूनों पर महत्वपूर्ण जानकारी और जागरूकता के लिए कमजोर वर्गों को सक्षम करने के लिए नवीन विचारों, उपकरणों और सरलीकृत पद्धति को एकीकृत कर रहा है।

उद्देश्य

कार्यक्षेत्र और वितरण के विस्तार के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग

विशेषज्ञ संस्थाओं के साथ साझेदारी करके विधिक साक्षरता को मुख्यधारा में लाना

मौजूदा जमीनी स्तर/फ्रंटलाइन कार्यबल/स्वयंसेवकों का क्षमता निर्माण और उपयोग

प्रभावशीलता को मापने के लिए संकेतक विकसित करना

समवर्ती मूल्यांकन और आवधिक मूल्यांकन

भागीदार एजेंसियां

- भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए), नई दिल्ली
राष्ट्रीय स्तर पर विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन।
- नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू), बंगलूरु, कर्नाटक
“डिजिटल कानूनी साक्षरता-प्रसार और आकलन”
- राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, भोपाल, मध्य प्रदेश
“डिजिटल विधिक साक्षरता-डिजाइन, विकास, प्रबंधन और परीक्षण –ई-न्यायगंगा”।
- राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एनएलयू), नई दिल्ली
“उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में प्रशिक्षण और जागरूकता सत्र आयोजित करना” (अधिकारों का ज्ञान प्रगति की पहचान)।
- अरुणाचल प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण (एपीएसएसएसए), इटानगर, अरुणाचल प्रदेश
“औपचारिक न्याय प्रदायनी प्रणाली पर गांव बुद्ध और गांव बुद्धियों की क्षमता निर्माण द्वारा “पारंपरिक ग्राम न्याय परिषद प्रणाली और भारत के औपचारिक कानूनों की प्रथागत के बीच तालमेल”।
- सिविकम राज्य महिला आयोग (एसएससीडब्ल्यू), गंगटोक, सिक्किम
“कर्मचारियों/छत्रों और स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के लिए “कार्यस्थल पर महिलाओं के रौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013, घरेलू हिंसा से महिलाओं की संरक्षण अधिनियम, 2005 मानव तस्करी रोध” पर प्रशिक्षण और संवेदीकरण कार्यक्रम।
- मनोविकित्सा विभाग, जवाहरलाल नेहरू विज्ञान विज्ञान संस्थान (जेएनआईएमएस), इम्फाल ईस्ट, मणिपुर
“प्रशिक्षण और जागरूकता सत्र आयोजित करके “बाल रौन शोषण के खिलाफ मीडियाकर्मियों, छात्रों, हितधारकों का प्रशिक्षण और संवेदीकरण”।
- सेंटर फॉर कम्युनिटी इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स सोसाइटी (सीकोडेकोन), जयपुर, राजस्थान
“राजस्थान के 5 आकांक्षी जिलों में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता को बढ़ावा देना”।
- शेडो एडवर्टाइजिंग एण्ड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, भुवनेश्वर, ओडिशा
ओडिशा राज्य में “अभिनव विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम”।
- यशवंतराव चव्हाण ग्राम विकास और प्रशासन लोक अकादमी (यशदा), पुणे, महाराष्ट्र
महाराष्ट्र की विभिन्न ग्राम पंचायतों में “विधिवत को बढ़ावा देना”।
- विधि अनुसंधान संस्थान (ईएलआरआई), गुवाहाटी, असम
“भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के प्रथागत प्रथाओं का दस्तावेजीकरण”।
- बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड), पटना, बिहार
ग्रामीण बिहार में विनिर्दिष्ट किए गए “विधि मित्रों को बढ़ावा देना”।
- अब्दुल नजीर साब राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, मैसूर, कर्नाटक
(सेटकॉम) प्रौद्योगिकी के माध्यम से “पंचायती राज संस्थान (पीआरआई) के प्रतिनिधियों का विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम का प्रशिक्षण और संवेदीकरण”।
- मेघालय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिलांग, मेघालय
सामुदायिक मध्यस्थता के माध्यम से न्याय तक पहुंच परियोजना।
- इंदिरा गाँधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली
इंदिरा गाँधी ओपन नेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा अमलीकृत “पैरालीगल प्रैक्टिस मजबूतीकरण परियोजना”।
- डॉ. अम्बेडकर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, पुडुचेरी
परियोजना “न्याया ओएलआई परियोजना-युवाओं के बीच कानूनी जागरूकता फैलाना”।

अंतर-मंत्रालयी अभिसरण



- 4 लघु फिल्मों विकसित की गई हैं। इन लघु फिल्मों का पंचायती राज मंत्रालय द्वारा भी प्रसार किया जा रहा है।



- न्याय विभाग द्वारा प्रदान की गई कानूनी साक्षरता सामग्री शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों के लिए वेब पोर्टल दीक्षा (स्कूली शिक्षा के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचा) पर अपलोड की गई है।

कानूनी जानकारी के लिए
सरलीकृत डिजिटल समाग्री



उत्ती सी हसी
<https://youtu.be/Pu6-jembih0>



जो मिल गया उसी को मुकदर समझ लिया
<https://youtu.be/mHKUHL0npKI>



लाखों तारे आसमान में
<https://youtu.be/y55gzl718Qs>



हम है रही प्यार के
<https://youtu.be/HI0RoBETkwo>

सामाजिक-कानूनी मुद्दों पर वेबिनार

न्याय विभाग द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय-स्तर के सामाजिक-कानूनी मुद्दों पर कानूनी जागरूकता वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किया गया है। अब तक न्याय विभाग ने बीस वेबिनार आयोजित किए हैं। इन बीस राष्ट्रीय-स्तरीय वेबिनारों के माध्यम से न्याय विभाग 4.62 से अधिक प्रतिभागियों तक पहुँच चुका है।



क्यू आर कोड के माध्यम से कानूनी जानकारी डिकोड करें



22 सितंबर, 2021 को 'घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम' 2005 पर आयोजित वेबिनार, 48,299+ प्रतिभागियों से संपर्क किया गया।

14 नवंबर, 2021 को 'बाल अधिकारों पर आयोजित वेबिनार' 17,644+ प्रतिभागियों से संपर्क किया गया।



26 नवंबर, 2021 को 'मौलिक कर्तव्य' विषय पर आयोजित वेबिनार, 24,082+ प्रतिभागियों से संपर्क किया गया।

7 जनवरी, 2022 को 'गर्भधारण और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम 1994' पर आयोजित वेबिनार, 15,080+ प्रतिभागियों से संपर्क किया गया।



18 फरवरी, 2022 को 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013' पर आयोजित वेबिनार, 19,158+ प्रतिभागियों से संपर्क किया गया।

8 मार्च, 2022 को 'भारत में लैंगिक न्याय' पर आयोजित वेबिनार, 35,332+ प्रतिभागियों से संपर्क किया गया।



25 अप्रैल, 2022 को 'कानून के साथ संघर्ष में बच्चे' पर आयोजित वेबिनार, 20,207+ प्रतिभागियों से संपर्क किया गया।

27 मई, 2022 को 'देखभाल एवं संरक्षण की जरूरत वाले बच्चे' पर आयोजित वेबिनार, 24,715+ प्रतिभागियों से संपर्क किया गया।





➤ 29 जून, 2022 को 'मानव तस्करी' पर आयोजित वेबिनार 30,627+ प्रतिभागियों से संपर्क किया गया।

31 अगस्त, 2022 को 'वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार' पर आयोजित वेबिनार, इसे 13,255+ लाभार्थियों से संपर्क किया गया।



➤ 28 अक्टूबर, 2022 को 'भारत में साइबर अपराध' पर आयोजित वेबिनार 30,442+ लाभार्थियों तक पहुंचा।

25 नवंबर, 2022 को 'संवैधानिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों' पर आयोजित वेबिनार 37,481+ लोगों तक पहुंचा।



➤ 27 दिसंबर, 2022 को 'भारत में विकलांग व्यक्तियों' के अधिकार पर आयोजित वेबिनार 16,612+ प्रतिभागियों तक पहुंचा।

30 जनवरी, 2023 को 'भारत में विवाराधीन कैदियों' के अधिकार पर आयोजित वेबिनार 17,960+ कार्यकर्ताओं तक पहुंचा।



➤ 6 मार्च, 2023 को 'ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और उनके अधिकारों का संरक्षण' पर आयोजित वेबिनार 29,851+ प्रतिभागियों तक पहुंचा।

28 मार्च, 2023 को 'उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण' पर आयोजित वेबिनार 21,143+ प्रतिभागियों तक पहुंचा।



➤ 12 जून, 2023 को 'भारत में बाल श्रम' पर आयोजित वेबिनार 25,133+ प्रतिभागियों तक पहुंचा।

18 जुलाई, 2023 को 'एसिड अटैक सर्वाइवर्स के पुनर्वास' पर आयोजित वेबिनार 15,127+ प्रतिभागियों तक पहुंचा।





➤ 29 सितम्बर, 2023 को 'श्रम कानून' पर आयोजित वेबिनार 2153+ प्रतिभागियों तक पहुंचा ।

31 अक्टूबर, 2023 को 'बाल यौन शोषण' पर आयोजित वेबिनार 33,318+ प्रतिभागियों तक पहुंचा ।



➤ 10 जुलाई, 2025 को 'साइबर अपराध और कानून: आधुनिक दुनिया में डिजिटल गिरफ्तारी को समझना' पर आयोजित वेबिनार 5000+ प्रतिभागियों तक पहुंचा ।

28 अगस्त, 2025 को 'न्याय तक पहुँच एक संवैधानिक जनादेश और एक लोकतांत्रिक अनिवार्यता' पर आयोजित वेबिनार 15,000+ प्रतिभागियों तक पहुंचा ।



➤ 25 सितंबर, 2025 को 'नए आपराधिक कानूनों के तहत बच्चों की सुरक्षा' पर आयोजित वेबिनार 24,000+ प्रतिभागियों तक पहुंचा ।

The collage features a variety of materials aimed at promoting women's rights and legal literacy. At the top, there are several booklets and posters. One booklet is titled 'कानून विचार' (Law Thinking) and another 'कानून विचार' (Law Thinking). There are also posters with the text 'STOP VIOLENCE AGAINST WOMEN' and 'लड़का लड़की के भेदभाव को दूर करें' (Eliminate discrimination between boys and girls). Below these, there are more posters and booklets, including one titled 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' (Save the Girl Child, Educate the Girl Child) and another titled 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' (Save the Girl Child, Educate the Girl Child). The bottom section of the collage contains two larger posters. The left one is titled 'LEGAL LITERACY AND LEGAL AWARENESS' and the right one is titled 'NATIONAL GIRL CHILD DAY'. Both posters provide information about legal literacy and legal awareness programs, including dates, times, and locations.

 @mlj_goi

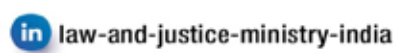
झलकियाँ राज्य स्तरीय कानूनी जागरूकता गतिविधियाँ



सोशल मीडिया से डिजिटल कानूनी साक्षरता
के लिए संपर्क करे **CEERA - NLSIU** का QR
कोड स्कैन करें



हमें फॉलो करें



समाचार में पैन इंडिया कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता

Union Justice Dept
campaign on Cons

ಗ್ರಾಮಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಪಂ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ
Koraput and it will run in other 8 districts of Odisha including Rayagada, Gajapati, Puri, Jagatsinghpur and Kendrapada districts of the state.
In several remote and interior villages of Odisha, peoples were least on partially aware about their basic rights. Through this IEC awareness campaign...

Awareness drive on consumer rights & sexual harassment
STATESMAN NEWS SERVICE
KORAPUT, 11 JANUARY
With an aim to create awareness on consumer's rights and sexual harassment of women at workplace, Department of Justice, Information & Communication (IEC) has organized an awareness drive...

Awareness drive on consumer rights & sexual harassment
STATESMAN NEWS SERVICE
KORAPUT, 11 JANUARY
With an aim to create awareness on consumer's rights and sexual harassment of women at workplace, Department of Justice, Information & Communication (IEC) has organized an awareness drive...

Union Justice Dept holds awareness campaign on Consumer Protection Act
PBD BUREAU
KORAPUT, JAN 11
organized in Koraput and this will run Rayagada, Gajapati, Ganjam, Khurda, Cuttack, Puri, Jagatsinghpur and Kendrapada districts of the state.

एनएलआईयू के 'ई-न्यायगंगा' से जानें क्या है सूचना अधिकार
जानें अपने अधिकार
भारत का कोई भी नागरिक नामांकित है 'सार्वजनिक प्रवर्तन' से जानकारी प्राप्त कर सकता है। यह जानकारी नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में सूचित करती है।

जनसूचना अधिनियम
15 Jan 2023 - Page 10
जनसूचना अधिनियम (RTI) भारत का एक महत्वपूर्ण कानूनी उपकरण है। यह नागरिकों को सरकारी सूचनाओं का अधिकार प्रदान करता है।

ವಕೀಲರಾದ ವಂಶವರಗದವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಬರಹ
ಬಾಗ್ಯೂರಿ ಮೂಲಕ: ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ.
The Union Justice Department has organized a campaign to create awareness about the Right to Information (RTI) Act, 2005.

समय समाज में किसी तरह की हिंसा स्वीकार नहीं, जागरूकता ही उपाय
हिंसा समाज में किसी तरह की हिंसा स्वीकार नहीं, जागरूकता ही उपाय। जागरूकता के माध्यम से हम हिंसा को रोक सकते हैं।

जनसूचना अधिनियम
15 Jan 2023 - Page 10
जनसूचना अधिनियम (RTI) भारत का एक महत्वपूर्ण कानूनी उपकरण है। यह नागरिकों को सरकारी सूचनाओं का अधिकार प्रदान करता है।

IEC awareness campaign on sexual harassment at workplace
STATESMAN NEWS SERVICE
BHUANESWAR, 25 JANUARY
With an aim to create awareness on consumer's rights and sexual harassment of women at workplace, the Department of Justice organized an IEC Awareness Campaign on "Consumer Protection Act, 2019" and "The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013".

विधिक साक्षरता जागरूकता पर जिला स्तरीय बैठक
विधिक साक्षरता जागरूकता पर जिला स्तरीय बैठक। जिला स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के लिए बैठक आयोजित की गई।

Workshop held on legal literacy and awareness
The Centre for Environmental Law & Pro Bono Club, and Law Nappur, organized one-day master trainer workshop on "Legal literacy and legal awareness" in association with "Legal Literacy, Ministry of Law and Justice, and the Department of Justice, Ministry of Law and Justice, and the Centre for Environmental Law, Education, Research and Advocacy (CEERA), NLSIU, Bengaluru, recently. Jaydip Govardhan Prof. Himanshu Pandey, Ashish J Dixit, Nappur, Prof. Venna Roshan J. were present. Pandey spoke on significance of legal awareness in the paradigm of social justice.

Free Psycho-Social counselling
IMPHAL, Mar 20
The Department of Psychiatry, JNIMS under the aegis of the Ministry of Law & Justice, Government of India is providing free specialized individuals, family and caregivers of Child Sexual Abuse from 10 am to 12.30 pm at OPD, 1st floor, JNIMS.

ಕೋಲಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ದಿನದ ಕಾನೂನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಯೋಜನೆ; ಪ್ರೇಮದೇವೇಂದ್ರ
ಕೋಲಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ದಿನದ ಕಾನೂನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಯೋಜನೆ.

The Legal Aid Clinic of Kirit P Mehta School of Law NMIMS recently organised a workshop in association with the Ministry of Law and Justice & CEERA-NLSIU
The Legal Aid Clinic of Kirit P Mehta School of Law NMIMS recently organised a workshop in association with the Ministry of Law and Justice & CEERA-NLSIU.

कायद्यावर आधारित शिबीर संपन्न
मुंबई : राज्य सरकार, शिबीर संपन्न। कायद्यावर आधारित शिबीर संपन्न।

ವಿಧವಾಕ್ಯ ನಾಣಕ ಗಾಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂದೇಶ
ವಿಧವಾಕ್ಯ ನಾಣಕ ಗಾಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂದೇಶ। ವಿಧವಾಕ್ಯ ನಾಣಕ ಗಾಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂದೇಶ।

more than 5,000 km of highway stretch
more than 5,000 km of highway stretch. more than 5,000 km of highway stretch.

ಕಾನೂನನ್ನು ಗೌರವಿಸದ ಕಾನೂನು ಸಮ್ಮುಖ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ
ಕಾನೂನನ್ನು ಗೌರವಿಸದ ಕಾನೂನು ಸಮ್ಮುಖ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ। ಕಾನೂನನ್ನು ಗೌರವಿಸದ ಕಾನೂನು ಸಮ್ಮುಖ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ।